

अनुलग्नक-1

(पैरा 2.1.1में संदर्भित)

2007-08 से 2017-18 तक संस्वीकृत अनुदान, निर्गत तथा प्रत्येक नाइपर द्वारा व्यय
दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ लाख में)

नाइपर का नाम	वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अहमदाबाद	संस्वीकृत	200	250	300	278	300	500	679	450	1776	1813	2296
	निर्गत	200	250	300	278	300	500	679	450	1776	1813	2296
	व्यय	100	295	322	288	312	434	456	519	1884	1938	2169
गुवाहटी	संस्वीकृत	0	100	1065	100	0	522	288	391	2100	2627	5200
	निर्गत	0	100	1065	100	0	522	288	391	2100	2627	5200
	व्यय	0	77	158	179	277	1061	373	418	2067	2668	4582
हाजीपुर	संस्वीकृत	0	0	0	0	0	45	370	400	600	600	600
	निर्गत	220	275	715	100	0	45	350	400	600	500	500
	व्यय	140	312	221	240	256	260	403	416	503	511	515
हैदराबाद	संस्वीकृत	350	2218	508	585	810	2030	2300	1417	3500	3500	3000
	निर्गत	350	2218	508	585	810	2030	2300	1417	3500	3500	3000
	व्यय	130	2215	473	584	735	2082	2245	1539	3511	3564	2730
कोलकाता	संस्वीकृत	200	148	300	160	350	450	500	450	630	800	1150
	निर्गत	150	150	348	160	309	175	441	438	630	800	1150
	व्यय	107	205	308	282	246	278	315	354	525	614	1125
मोहाली	संस्वीकृत	एनए	1739	2123	2064	2477	2282	1920	2087	2748	2748	2831
	निर्गत	एनए	1739	2123	2064	2477	2282	1920	2087	2748	2748	2831
	व्यय	एनए	1979	2668	2447	2883	3010	3353	3113	4089	3952	3913
रायबरेली	संस्वीकृत	0	0	0	0	650	450	450	445	700	700	850
	निर्गत	0	250	280	428	300	350	450	445	550	625	950
	व्यय	0	194	399	348	360	375	320	395	590	525	897
कुल योग	संस्वीकृत	750	4455	4296	3179	4587	6279	6507	5640	12054	12788	15927
	निर्गत	920	4982	5339	3707	4196	5904	6428	5628	11904	12613	15927
	व्यय	477	5277	4549	4368	5069	7500	7465	6754	13169	13772	15931

अनुलग्नक-II

(पैरा 4.1.6.1 (ग) में संदर्भित)

परियोजनाओं के संदर्भ में दी गई वित्तीय सहायता जिसके लिए एसआरपी का गठन नहीं किया गया।

(रु करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	संस्वीकृत ऋण	वित्तीय वर्ष में वित्तरित राशि
1.	हरियाणा (एसआरपी अभी तक लंबित)	2012-13	10	869.53	623.36	335.73
2.		2013-14	-	-	-	353.44
3.		2014-15	-	-	-	186.97
4.		2015-16	10	1607.49	1238.97	165.14
5.		2016-17	-	-	-	521.65
योग (i)						1562.93
6.	राजस्थान	2012-13				61.75
7.	(एसआरपी) 10	2013-14	5	278.27	208.7	2.00
8.	नवम्बर 2015	2014-15				1.69
9.	को प्रकाशित	2015-16				0
10.		2016-17				0
योग (ii)						65.44
11.	जीएनसीटीडी	2012-13				0
12.	(जिसमें	2013-14	1	101.65	76.24	0
13.	एसआरपी तैयार	2014-15				20.00
14.	नहीं किया गया	2015-16				0
15.	है)	2016-17				0
योग (iii)						20.00
कुल योग (i+ii+iii)						1648.37

अनुलग्नक-III

{अनुच्छेद 4.1.6.1 (ज) में संदर्भित}
लेखापरीक्षा परिणाम का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कर्ज सहयोग/अनमोदित दिनांक	जारी कर्ज/दिनांक	कर्ज की प्रतिबंध व शर्त	लेखापरीक्षा अवलोकन	मंत्रालय/बोर्ड का जवाब (जनवरी 2018/नवंबर 2017)	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
कर्ज स्वीकृति पत्र के प्रतिबंध व शर्तों को पूर्ण किये विना कर्ज को जारी करना							
1.	जिला मेवात, हरियाणा शैक्षणिक अस्पताल संग चिकित्सा कालेज के निर्माण परियोजना	₹239.18 करोड़/09 जून 2009	₹113.33 करोड़/18 नवंबर 2010	योजनाओं के निर्माण, भूमि उपयोग परिवर्तन बजट स्वीकृति पत्र, पर्यावरण अनुमति इत्यादि के अधीन कर्ज स्वीकृत किया गया।	योजनाओं के लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा की गई जवाब में कहा कि बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम कर्ज की किशत को जारी करने से पहले, पर्यावरण अनुमति व भूमि से पहले कर्ज सहयोग के प्रविर्तन आदि सभी प्रतिबंध व शर्तों का अवलंबित थे। फिर भी बोर्ड अधिकाारियों ने (18 नवंबर 2010) को राज्य सरकार को 113.33 करोड़ रुपये के कर्ज जारी किए। परियोजना 21 मई 2015 को पूरी हुई और अब प्रचालित है।	बोर्ड/मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम कर्ज की किशत को जारी करने से पहले, पर्यावरण अनुमति व भूमि से पहले कर्ज सहयोग के प्रविर्तन आदि सभी प्रतिबंध व शर्तों का अवलंबित था। फिर भी बोर्ड अधिकाारियों ने (18 नवंबर 2010) को अनुसार परियोजना की निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एंजेसी को सुचारु सहयोग दिया जाएगा।	बोर्ड व मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने कर्ज की किशत के आवंटन से पहले, स्वीकृति पत्र के प्रतिबंध व शर्तों का मिलान सुनिश्चित नहीं किया।

2.	उत्तर प्रदेश में पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) द्वारा हापुड़ में आनंद विहार आवासीय गृह योजना	₹133.80 करोड़	₹50करोड़ (अगस्त 2008 व मार्च 2009 के दौरान ₹37.50 करोड़ व ₹12.50 करोड़ की इत्यादि दो मूलभूत सुनिश्चित क्रमशः जारी किशते की गई)	पीएसएमजी कहा आवासीय योजना के लिए आपूर्ति, विकास का ढाँचा सुनिश्चित समापन व लक्ष्य के समकालिक व समापन के साथ होना चाहिए।	ने देखा कि एचपीडीए ने निर्माण नहीं किया और एचपीडीए ने सुझाव दिया कि आवासीय विहार के स्त्राव को पश्चिमी छोर की तरफ बहने वाले बड़े नाले से जोड़ दिया जाएगा। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के खिलाफ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी घरेलू और औद्योगिक कचरे के शोधन से पहले भूमि या जल निकायों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अतः ऋण की संवितरण और उपयोग के समय बोर्ड द्वारा पीएसएमजी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।	बोर्ड ने कहा कि बोर्ड (30 दिसंबर 2015) ने एचडी पीए से निवेदन किया है कि परियोजना क्षेत्र में जल निकास की उपचार के संबंध में तुरंत कार्रवाई करें और एसटीपी के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता पर शुरू करें।	बोर्ड का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि डीपीआर के अनुसार एसटीपी के निर्माण के लिए एक प्रावधान था और पी एसएमजी ने अपने 40वें मीटिंग में एसटीपी के निर्माण पर भी जोर दिया, फिर भी परियोजना के समापन के तीन साल बाद भी एसटीपी का निर्माण नहीं हो पाया। परन्तु बोर्ड द्वारा इस मुद्दे को आईए के साथ दिसम्बर 2015 से नहीं उठाया गया।
----	---	---------------	--	---	--	---	---

आईए को भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद भी कर्ज का अनुदान			
3.	राजस्थान में अलवर जल आपूर्ति सुधार परियोजना	₹131.14 करोड़/19 नवंबर 2013	₹51 करोड़/30 सितंबर 2016
			<p>बोर्ड ने (30 सितंबर 2016) को बोर्ड के अधिकारियों के भौतिक व वित्तीय सत्यापन के स्वरूप (23 सितंबर 2016) ₹43.72 करोड़ की लोन की दक्षिण किशत जारी कर दी। लेखापरीक्षा ने कि (30 मार्च 2017) पीएचडी अलवर नगर अधीन छः स्थानों पर कार्य आरंभ नहीं था जहाँ भी यूआईटी द्वारा राजस्थान को नहीं हुई। वास्तव जारी करने से आईए अपेक्षित भूमि को सत्यापन के</p> <p>बोर्ड ने अपने जवाब में कहा कि इस परियोजना एक सरकारी संस्था दूसरी में भूमि हस्तांतरण शामिल था। आइए ने पुष्टि की जल्दी ही बचे हुए स्थलों को भी जाने की आशा है।</p> <p>बोर्ड और मंत्रालय का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अनुमोदन के पाँच वर्ष के बीत जाने के भी, बावजूद अपेक्षित भूमि आईए के अधिपत्य में नहीं है। परियोजना अभी भी उन्नति पर है (जून 2019)</p>

4.	हरियाणा नलहार चिकित्सा कॉलेज तथा नुह टाऊन के लिए जल आपूर्ति योजना	₹79.21 करोड़/04 अगस्त 2011	₹90.13 करोड़/30 सितम्बर 2016 तक	भूमि हरियाणा सरकार के कब्जे में होनी चाहिए और वैधानिक मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए	यह आकलन और सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि भूमि आईए के कब्जे में है। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि बोर्ड ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि क्या ₹90.13 करोड़ का ऋण किस्त करने से पहले भूमि कार्यन्वयन एजेंसी के कब्जे में थी। असल में 02 फरवरी 2017 तक, 20 एकड़ की अपेक्षित भूमि में से केवल 14.50 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि अपेक्षित अनुमोदन लंबित थे, बोर्ड ने (30 सितंबर 2016) बोर्ड के अधिकारियों द्वारा आयोजित भौतिक और वित्तीय सत्यापन की सिफारिश (23 सितंबर 2016) पर ₹22 करोड़ की तीसरी किस्त जारी की	बोर्ड ने अपने पहले उत्तर में कहा था (अक्टूबर 2017) कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी उप परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए नए भूमि अधिग्रहण (एलएए) 2013 के आवेदन पर अस्पष्टता के कारण हुई।	बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2011 में ऋण अगस्त 2014 में पूरा किया जाने के लिए, इस शर्त के साथ दिया गया था कि भूमि कब्जे में थी, इसके बाद किस्तों को भूमि के कब्जे को सुनिश्चित किए बिना जारी किया गया। परियोजना अभी भी प्रगति पर है (जून 2019)
----	---	----------------------------	---------------------------------	--	--	--	---

वित्तीय हितों की रक्षा के लिए समझौते/प्रासंगिक खंडों का अभाव						
5.	हरियाणा राज्य में रेवाड़ी कोट कासिम रोड एनएच-8 तक, शंहजहांपुर, रेवाड़ी नरनाल रोड 6 किमी. तक (एसएच 26) रेवाड़ी मोहिंदर नगर रोड, रेवाड़ी दादरी रोड प्रस्तावित बाई पास तक चार लेन बनाने के माध्यम से सुधार	₹79.55 करोड़/नवंबर 2008	₹67.55 करोड़/3 जुलाई 2009	परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी।	बोर्ड द्वारा वितरित ऋण परियोजना की प्रगति से जुड़ा नहीं था तथा परियोजना में देरी के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। परियोजना के पूरा होने में पाँच साल की देरी थी। परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि नवंबर 2010 थी तथा परियोजना के पूरा होने की वास्तविक तिथि 10 फरवरी 2016 थी। परियोजना को पूरा करने में भारी देरी के बावजूद बोर्ड ने (31 मार्च	मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अपने पहले जवाब में पृष्ठ की कि कार्यान्वयन एजेंसी के अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके कार्य का निष्पादन रोक दिया, जिसके कारण काम में देरी हुई। परियोजना को पूरा करने में भारी देरी के बावजूद बोर्ड ने (31 मार्च 2016) को ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की।
				मंत्रालय/बोर्ड ने यह जवाब दिया कि मंजूरी पत्र में जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था क्योंकि परियोजनाएं जोकि बोर्ड द्वारा वित्तपोषित है वह जनकल्याण उन्मुख है। परियोजना के दौरान होने वाली देरी कुछ व्यावहारिक मुद्दों के कारण होती है जो कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकती है।		

6.	सराय काले खाँ तथा आनंद विहार पर मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर (एमएमटीसी) परियोजनाएँ	--	परिवहन विभाग, दिल्ली के अनुरोध पर सराय काले तथा आनंद विहार पर मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर परियोजनाएं। इन परियोजनाओं को विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन	2016) में ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की।	एडीबी की शर्तों के अनुसार, प्रतिबद्धता शुल्क असंवितरित राशि पर लगाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया की प्रतिबद्धता शुल्क के भुगतान के बारे में बोर्ड ने जीएनसीटीडी के साथ कोई समझौता नहीं किया था, जिसके फलस्वरूप, जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग की गैर स्टार्टर परियोजनाओं के कारण जीएनसीटीडी की ओर से, बोर्ड ने	मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाँच साल से अधिक का समय बीतने के बावजूद, बोर्ड जीएनसीटीडी से बकाया राशि वसूलने में असमर्थ था। बोर्ड का जवाब निर्माण योजना की भूमि के उपयोग के परिवर्तन और मंजूरी सुनिश्चित किए बिना ऋण के अनुमोदन पर मौन था।
		₹69.96 लाख प्रतिबद्धता शुल्क के रूप में/31 जनवरी 2013		2016) में ₹4.22 करोड़ की अंतिम किस्त जारी की।	मंत्रालय/बोर्ड ने अपने जवाब में यह कहा कि मामला विचाराधीन है और नियमित अनुवर्ती कार्यवाही चल रही है ताकि जीएनसीटीडी से उक्त प्रतिबद्धता शुल्क की वसूली सुनिश्चित हो सके।	

				और भवन योजनाओं की मंजूरी के बिना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।	(31 जनवरी 2013) ₹69.96 लाख का प्रतिबद्धता शुल्क भुगतान किया।		
आरपी 2021 के किसी भी तत्व के तहत परियोजना का वित्तपोषण शामिल नहीं होना							
7.	कड़कड्डमा औद्योगिक शाहदरा एनसीटीडी बहुमंजलीय इमारत का निर्माण	₹76.24 करोड़/30 दिसंबर 2013	₹20 करोड़/02 सितंबर 2014	परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि सितंबर 2016 थी।	लेखापरीक्षा ने पाया की अप्रैल 2017 तक उक्त कार्य को ना तो आबंटित किया गया ना ही शुरू किया गया। कार्य को अक्टूबर 2017 में आबंटित किया गया। एक नागरिक एजेंसी के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए धन आरपी 2021	मंत्रालय तथा बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आर.पी. 2021 के किसी भी तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। परियोजना अभी भी जारी है। (जून 2019)	ने अपने जवाब में कहा कि परियोजना पर निम्नलिखित आधार पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया गया है:- 1. शहर के केन्द्रीय व्यापार जिले में प्रस्तावित पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के

					<p>के विभिन्न तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है।</p>	<p>कार्यालय परिसर के निर्माण की साइट एमपीडी-2021 के शहरी क्षेत्र के भीतर आती है।</p> <p>2. एनसीआरपीवी अधिनियम 7(ई) तथा 8 (ई) के अनुसार बोर्ड और एनसीआर सीएमए में बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के लिए घटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एंजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

अनुलग्नक -IV
(पैरा 4.2.3 में संदर्भित)
अतिरिक्त मदों की विवरणी जो कि मुख्य समझौते में शामिल नहीं की गई

क्रम संख्या	प्रस्तुत अतिरिक्त मदों का ब्योरा	प्रस्तुत मात्रा	दर्शाई गई दर	अदा की गई मात्रा (₹ लाख में)	सीपीडब्लूडी द्वारा दिए गए तर्क	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	प्लस्टर वाली दिवार की सतह पर सफेद सीमेंट मिली पुष्टी जिसकी औसत मोटाई 1 मि.मी हो, मुहैया व प्रयोग कराना ताकि सतह समतल व एक समान पूरी हो।	74,872.99 वर्ग मीटर	86.20 प्रति वर्ग मीटर	64.54	सभी मकानों की आंतरिक दीवारों व छतों की तह में सीमेंट मिली पुष्टी लगाना, आवश्यक है और यह ग्राहक विभाग की तरफ से भी जरूरी बताया गया है।	मुख्य रूप से 184 आवासीय मकानों के निर्माण का यह कार्य था और सफेद सीमेंट की पुष्टी ऐसे कार्य में मूलभूत आवश्यकता थी। सीपीडब्लूडी ने विस्तृत आकलन व एनआईटी स्वीकृत करने के समय में इस बात को महत्व नहीं दिया और इस कार्य को एक अतिरिक्त मद के बतौर पूर्ण किया।

2.	सभी फर्श सतहों पर विभिन्न व्यासों के पाइपों को लगाने की आवश्यकता व प्रभारी के निर्देशानुसार मूठ कटिंग मशीन व औजारों का प्रयोग करते हुए आरसीसी दीवारों, फर्श व छतों की पहिया पर कोर कटिंग देना। (अ) स्थल की आवश्यकतानुसार व्यास व गहराई का 100 से 150 मिमी.	1065 मी.	1017.09 प्रति मीटर	10.83	इस मद को तकनीकी रूप से दीवारों में छेद/आरसीसी स्लैब आदि के आवश्यक माना जाता है।	इस तरह के मद को शामिल न करना यह दर्शाता है कि परियोजना की आवश्यकता के पूर्ण संज्ञान के साथ विस्तृत आंकलन तैयार नहीं किया गया था।
3.	खिड़कियों में आवश्यक पैटर्न के फ्रेम के अनुरूप एमएस गिल गढ़ना और लगाना, साथ ही स्वीकृत स्टील प्राइमर के साथ एमएस फ्लैट्स स्क्वायर या राउंड बार सहित।	44,424.91 किलो ग्राम	115.25 प्रति किलो ग्राम	51.20	सभी बकाया मदों के आकलन में जो कार्य समापन के लिए स्थल पर कार्यान्वयन के लिए जरूरी थे, इस मद को भी लिया गया लेकिन हर फर्श पर ढाँचे की आवश्यकता होने के कारण दूसरी एजेसियों से	विस्तृत आकलन/ एनआईटी की स्वीकृति के समय सभी जरूरी मदों पर विचार नहीं किया गया और सीपीडब्लूडी द्वारा इस मद को ध्यान नहीं दिया गया। यदि इस मद को विस्तृत आकलन/ एनआईटी में शामिल किया गया होता तो बाजार भाव

						अदायगी से बचा जा सकता था।
						इस मद को कार्यान्वित करना यह बहुत ही मुश्किल है
4.	सामने की दीवार पर बिना प्लास्टिक कठोर पीवीसी रेनवाटर पाइप जो आईएस 13592 टाइप (ए) के समरूप है का देना व लगाना और जिसमें 10 मि.मी. के ऊष्मा प्रसार के लिए जगह छोड़कर सील रिंग जो आईएस: 5382 के समरूप है, जोड़ना शामिल है (ए) सिंगल सॉकेट पाइप 75 मि.मी. ब्यास	787.28 मीटर	141.25 प्रति मीटर	1.11	एडीजी सीपीडब्लूडी के स्थल निरीक्षण के दौरान ये बात रखी गई कि पानी निकासी के लिए बालकनी में 75 मि.मी. ब्यास के पीवीसी पाइप लगाए जाए। इस प्रकार समझौते में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह अतिरिक्त मद के रूप में किया गया।	लेखापरीक्षा का यह मत है कि बालकनी से पानी निकास करवाना, निर्माण का एक मूलभूत व आवश्यक मद है, जो सीपीडब्लूडी ने विस्तृत आंकलन बनवाते समय नहीं देखा।
5.	प्रभारी के निर्देशानुसार कील आदि के साथ शीशे के पल्ले 4 मि.मी. मोटे फ्लोर ग्लास का मुहैया कराना व लगाना।	364.51 वर्ग मी.	655.91 प्रति वर्ग मीटर	2.39	सभी ब्लाकों में कूलर व एसी के प्रावधान के लिए खिड़कियों के खोलने में मद की जरूरत है। मद को समझौते में नहीं लिया गया अतः अतिरिक्त माना जाए।	यह प्रावधान खिड़की का अभिन्न हिस्सा था और सीपीडब्लूडी ने चूक कर दी, परिणामस्वरूप अतिरिक्त मद में लिया गया।

6.	बाहरी दिवारों के प्लस्टर के लिए जमीन सतह से 10 मी. से अधिक की ऊँचाई के ऊपर प्रत्येक 3 मी. या उससे ऊपर की अतिरिक्त ऊँचाई	10,041.52 वर्ग मीटर	39.11 प्रति वर्ग मीटर	3.93	लिफ्ट शाफ्ट के प्लस्टर के लिए मद की परंतु मद समझौते के अन्तर्गत नहीं लिया गया।	लिफ्ट शाफ्ट में प्लस्टर आवश्यक था किंतु सीपीडब्लूडी द्वारा चूक गया।
	कुल			(₹134.00 लाख अथवा ₹1.34 करोड़)		

अनुलग्नक-V

(पैरा 4.4 में संदर्भित)

अप्रैल 2007 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान परिहार्य व्यय

क्रम स.	विवरण	मिंटो रोड मुद्रणालय	मायापुरी मुद्रणालय
1.	ली गई अनुबंधित मांग	1000 केवीए	802 केवीए
2.	आवश्यक अधिकतम अनुबंधित मांग	350 केवीए	400 केवीए
3.	शेष अप्रयुक्त अनुबंधित मांग	650 केवीए	402 केवीए
4.	दर प्रति केवीए: (i) अप्रैल 2007 से अगस्त 2011 (53 महीने) (ii) सितंबर 2011 से अगस्त 2017 (72 महीने) (iii) सितंबर 2017 से मार्च 2018 (7 महीने)	₹150/केवीए ₹125/केवीए ₹130/केवीए	₹150/केवीए ₹125/केवीए ₹130/केवीए
5.	परिहार्य नकद हानि: (i) ₹150 x 53 महीने x 650 केवीए = ₹51,67,500 (ii) ₹125 x 72 महीने x 650 केवीए = ₹58,50,000 (iii) ₹130 x 07 महीने x 650 केवीए = ₹5,91,500 (i) ₹150 x 53 महीने x 402 केवीए = ₹31,95,900 (ii) ₹125 x 72 महीने x 402 केवीए = ₹36,18,000 (iii) ₹130 x 07 महीने x 402 केवीए = ₹3,65,820	₹1,166,09,000	₹71,79,720
	कुल		₹1,87,88,720

कुल परिहार्य नकद हानि ₹1,87,88,720 अथवा ₹1.88 करोड़

अनुलग्नक-VI

(पैरा 4.5.1 में संदर्भित)

2014-15 की समाप्ति पर बकाया मुद्रण प्रभारों तथा उनके सापेक्ष में 2015-16 तथा 2016-17 में वसूली का वर्ष-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	वर्ष	वर्ष 2014-15 के अंत में बकाया शेष	2016-17 के अंत में बकाया शेष	2014-15 के अंत में बकाया देय, जो 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त हुए	2017-18 के अंत में बकाया शेष
1.	1976-77 से 1989-90	2,05,41,981	2,05,41,981	0	2,05,41,981
2.	1990-91	2,53,789	2,53,789	0	2,53,789
3.	1991-92	17,02,646	17,02,646	0	17,02,646
4.	1992-93	31,28,706	31,28,706	0	31,28,706
5.	1993-94	28,48,869	28,48,869	0	28,48,869
6.	1994-95	11,06,703	11,06,703	0	11,06,703
7.	1995-96	7,50,990	7,50,990	0	7,50,990
8.	1996-97	35,58,056	35,58,056	0	35,58,056
9.	1997-98	61,01,292	61,01,292	0	60,97,578
10.	1998-99	35,78,687	35,78,687	0	35,78,687
11.	1999-2000	39,58,765	39,58,765	0	39,58,765
12.	2000-01	59,29,416	59,29,416	0	59,29,416
13.	2001-02	1,75,49,573	1,75,47,024	2,549	1,75,47,024
14.	2002-03	61,10,899	61,10,899	0	61,10,899
15.	2003-04	42,66,431	42,66,431	0	42,66,431
16.	2004-05	34,28,078	34,20,459	7,619	32,75,184
17.	2005-06	62,13,323	51,22,280	10,91,043	51,22,280
18.	2006-07	67,47,091	60,22,476	7,24,615	60,22,476
19.	2007-08	1,10,81,761	1,06,98,249	3,83,512	1,06,98,249
20.	2008-09	1,01,53,758	94,61,610	6,92,148	94,61,610
21.	2009-10	60,12,478	59,25,065	87,413	58,72,418
22.	2010-11	30,91,945	29,50,703	1,41,242	29,50,703
23.	2011-12	1,05,33,280	1,00,90,849	4,42,431	1,00,38,516

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

24.	2012-13	1,67,78,741	1,66,43,740	1,35,001	1,66,43,740
25.	2013-14	30,25,22,050	6,92,86,112	23,32,35,938	5,26,33,972
26.	2014-15	44,06,02,993	28,70,17,969	15,35,85,024	14,93,59,963
27.	2015-16	लागू नहीं	28,49,04,111	लागू नहीं	28,29,45,798
28.	2016-17	लागू नहीं	17,25,33,917	लागू नहीं	10,32,56,708
29.	2017-18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20,77,54,368
	कुल	89,85,52,301	96,54,61,794		94,74,16,525

अनुलग्नक-VII

(पैरा 4.5.4 में संदर्भित)

2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के अंत में मुद्रण प्रभारों की बकाया वसूलियों का संगठन-वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग या संगठन का नाम जिनसे मुद्रण प्रभार की वसूली की जानी थी	31.03.15 को बकाया शेष	31.03.16 को बकाया शेष	31.03.17 को बकाया शेष	31.03.18 को बकाया शेष
1.	कृषि	1,49,73,144	1,41,76,098	1,49,13,262	1,59,28,472
2.	परमाणु ऊर्जा	0	0	1,04,017	1,16,757
3.	आयुष	0	0	2,76,093	3,36,479
4.	बीएसएनएल	9,41,030	9,41,030	9,84,115	9,84,115
5.	भारतीय मानक ब्यूरो	63,653	63,653	1,40,176	3,20,283
6.	कैबिनेट सचिवालय	1,55,973	3,09,660	1,90,510	2,24,388
7.	रसायन एवं उर्वरक	1,27,149	3,26,585	7,15,801	11,94,951
8.	नागर विमानन	3,59,521	4,56,888	7,20,239	11,07,972
9.	नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं लोक वितरण	2,350	2,350	2,350	2,350
10.	कोयला एवं खान	1,60,860	2,19,637	3,29,156	11,67,712
11.	वाणिज्य एवं उद्योग	56,94,913	39,42,732	65,92,100	1,51,73,061
12.	संचार एवं	56,83,488	47,99,327	55,73,767	58,82,281

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

	सूचना प्रौद्योगिकी				
13.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	2,06,857	3,16,539	5,28,097	15,49,958
14.	कॉरपोरेट मामले	69,916	1,35,623	6,68,126	30,72,706
15.	संस्कृति	2,04,868	1,05,434	5,31,737	8,08,541
16.	रक्षा	9,65,18,835	11,30,40,549	10,99,18,995	12,29,87,466
17.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	0	0	1,30,034	1,30,034
18.	पेय जल एवं स्वच्छता	1,19,151	51,375	2,41,353	2,25,486
19.	पृथ्वी विज्ञान	0	0	1,06,821	1,14,405
20.	भारत का चुनाव आयोग	0	0	2,23,901	9,78,659
21.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	0	0	1,38,904	1,38,904
22.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	32,62,638	36,80,918	1,15,10,214	1,79,47,550
23.	विदेश मंत्रालय	4,03,201	4,84,182	6,90,093	13,17,816
24.	परिवार न्यायालय	0	0	2,12,013	2,12,013
25.	वित्त	1,15,74,211	1,18,01,048	2,40,49,758	3,23,33,270
26.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	50,282	50,282	50,282	50,282
27.	खाद्य एवं उपभोक्ता मामले	3,099	3,099	3,099	3,099
28.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	7,16,070	5,53,550	3,20,230	2,28,712

29.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	97,02,560	1,01,66,604	1,77,64,191	1,92,64,668
30.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	6,20,493	7,10,357	9,49,422	8,66,381
31.	गृह मंत्रालय	2,22,66,147	2,08,58,350	2,76,92,755	6,88,37,457
32.	आवासन एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	0	0	96,349	10,96,415
33.	मानव संसाधन विकास	3,30,98,623	3,40,68,467	3,57,80,279	4,23,27,406
34.	उद्योग	25,129	25,129	25,129	25,129
35.	सूचना एवं प्रसारण	3,60,631	2,93,630	4,95,931	3,31,589
36.	श्रम	13,767	13,767	13,767	13,767
37.	श्रम एवं रोजगार	10,64,340	3,91,180	11,60,188	38,19,631
38.	न्याय एवं विधि	24,64,568	26,97,006	24,89,190	30,50,178
39.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	57,191	1,59,015	1,90,448	8,75,757
40.	खान	1,00,72,833	13,35,514	7,13,538	6,76,029
41.	अल्पसंख्यक मंत्रालय	0	0	2,56,871	2,88,725
42.	एनसीटीडी (दिल्ली गजट)	48,49,926	12,54,733	66,66,003	56,15,753
43.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,78,29,259	1,52,45,679	4,65,76,176	4,44,92,266
44.	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	0	96,875	1,16,528	1,20,054
45.	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	5,05,937	5,05,937	5,05,937	5,05,937
46.	प्रवासी भारतीय मामले	37,640	0	0	0

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

47.	संसदीय मामले	6,838	6,838	66,986	1,47,651
48.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	53,49,542	53,99,685	48,19,733	59,28,094
49.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	4,67,322	5,44,418	52,90,414	87,81,359
50.	योजना (नीति) आयोग	1,31,078	1,31,078	97,112	97,112
51.	विद्युत	55,055	93,004	3,44,824	6,34,433
52.	राष्ट्रपति का सचिवालय	0	0	10,578	73,655
53.	पंचायती राज	0	0	44,711	44,711
54.	रेलवे	35,81,191	30,76,957	1,39,12,197	1,01,14,163
55.	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार	19,857	19,857	19,857	19,857
56.	ग्रामीण विकास	25,72,111	25,04,016	27,83,615	28,85,702
57.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3,53,036	3,53,036	5,64,374	3,67,938
58.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	16,20,202	15,46,164	3,04,43,406	5,53,50,287
59.	पोत परिवहन	0	0	5,53,258	8,33,109
60.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	0	84,650	3,25,366	3,52,875
61.	लघु उद्योग	27,203	27,203	27,203	27,203
62.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	3,35,654	59,517	7,30,659	10,94,250
63.	अंतरिक्ष	0	0	1,27,775	1,39,151
64.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन	16,83,750	14,66,555	12,12,790	11,36,600
65.	इस्पात एवं खान	87,396	29,935	78,970	1,38,080
66.	आपूर्ति एवं पुनर्वास	28,143	28,143	28,143	28,143

67.	सर्वोच्च न्यायालय	0	0	7,052	19,393
68.	भूतल परिवहन	2,940	2,940	2,940	2,940
69.	वस्त्र	1,75,414	2,12,677	67,8,354	9,01,669
70.	तीस हजारी न्यायालय	4,20,275	3,83,511	42,84,942	25,26,533
71.	पर्यटन एवं संस्कृति	2,63,075	2,63,075	4,45,015	3,65,503
72.	आदिवासी मामले	2,73,723	4,48,870	4,26,774	4,26,774
73.	शहरी विकास (प्रकाशन नियंत्रक)	62,65,78,838	67,25,31,722	56,44,59,943	42,49,12,399
74.	संघ लोक सेवा आयोग	35,15,311	12,18,368	30,59,142	30,59,142
75.	शहरी विकास	60,50,286	66,88,856	75,47,442	79,54,677
76.	जल संसाधन	1,72,408	1,89,945	5,94,309	8,16,670
77.	कल्याण	2,45,563	2,45,563	2,45,563	2,45,563
78.	महिला एवं बाल विकास	2,64,011	59,805	6,07,457	7,26,874
79.	युवा मामले एवं खेल	11,826	1,99,477	2,62,945	5,19,151
	कुल योग	89,85,52,301	94,10,98,667	96,54,61,794	94,74,16,525

अनुलग्नक-VIII

(पैरा 4.5.4 में संदर्भित)

जीएनसीटीडी से बकाया मुद्रण प्रभारों का वर्ष-वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	वर्ष	एनसीटीडी (दिल्ली गजट)	एनसीटीडी
1.	1976-77 से 1989-90	0	31,20,469
2.	1990-91 से 1999-2000	4,26,036	13,48,110
3.	2000-01 से 2009-10	3,89,725	55,86,130
4.	2010-11	10,473	0
5.	2011-12	0	3,09,256
6.	2012-13	11,024	0
7.	2013-14	0	9,57,877
8.	2014-15	0	5,11,299
9.	2015-16	0	2,85,221
10.	2016-17	13,24,280	78,04,035
11.	2017-18	34,54,215	2,45,69,869
	31 मार्च 2018 को कुल देय	56,15,753	4,44,92,266

अनुलग्नक-IX

(पैरा 4.9 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा और डीडीए द्वारा दुरुपयोग प्रभार की गणना

ब्योरा	नीति के अनुसार फार्मुला	अभियुक्तियाँ
डीडीए के रिकार्ड में उपलब्ध ₹6.24 लाख की गणना	<p>आधारभूत दर X दुरुपयोग तहत कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में X समय कारक X ऐतिहासिक कारक</p> <p>₹11,200 X 181.86 वर्ग मीटर 1.5 X 0.5 = ₹15,27,624</p> <p>1 जनवरी 1983 से 31 दिसम्बर 1989 (72 माह)</p> <p>दुरुपयोग प्रभार = ₹15,27624/210X72 = ₹5,23,757 ----- (i)</p> <p>1 जनवरी 1990 से 5 जुलाई 2000 (138 माह)</p> <p>दुरुपयोग प्रभार = ₹15,27,624/210 X 138 = ₹10,03,867 ----- (ii)</p> <p>(ii) का 10% = ₹1,00,387 ----- (iii)</p> <p>कुल दुरुपयोग प्रभार = (i) + (iii) = ₹6,24,144</p>	<p>कुल दुरुपयोग क्षेत्र 727.42 वर्ग मीटर का 25% लिया गया यह मानते हुए कि दुरुपयोग क्षेत्र नियम-III के अन्तर्गत विवादित था।</p> <p>1 जनवरी 1990 से 5 जुलाई 2000 की अवधि के लिए दुरुपयोग प्रभार कुल राशि का 10% गणना किया गया दुरुपयोग नीति के क्लॉज 5 के आधार पर जोकि बताता है कि जहाँ सम्पत्ति बिना मालिक के जानकारी या सुविधा के बिना किरायेदार द्वारा दुरुपयोग किया गया तथा मालिक ने निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया हो जिसमें कि सम्पत्ति का दुरुपयोग होना निष्कासन का एक आधार हो वहाँ दुरुपयोग प्रभार 10% लगाया जाना चाहिए।</p>
लेखापरीक्षा द्वारा गणना	<p>आधारभूत दर X दुरुपयोग तहत कुल क्षेत्र वर्ग मीटर में X समय करक X ऐतिहासिक कारक</p> <p>₹11,200 X 872.80 वर्ग मीटर X 1.5 X 0.50 अर्थात ₹73,31,520</p> <p>घटाव: भुगतान की गई राशि (₹10,00,000 + ₹99,728) = ₹10,99,728</p> <p>दुरुपयोग प्रभार = ₹62,31,729</p>	<p>डीडीए द्वारा अनुमोदित कुल दुरुपयोग 872.20 वर्ग मीटर क्षेत्र था।</p>

2020 की प्रतिवेदन सं. 3

1. आधारभूत दर नीति के तहत दिया गया था और दक्षिणी दिल्ली के क्षेत्रों के लिए आधारभूत दर ₹11,200 था।
2. नीति में समय कारक शून्य से पांच वर्ष के लिए एक, पांच से 10 वर्ष के लिए 1.25 और 10 वर्ष से ज्यादा के लिए 1.5 था।
3. नीति में दिए गए ऐतिहासिक कारक निम्नलिखित था:

दुरुपयोग की अवधि (वर्ष में)	ऐतिहासिक कारक
1.4.1985 से पहले	0.25
1.4.1985 से 31.3.1995 तक	0.50
1.4.1995 से 31.3.2005 तक	0.75
1.4.2005 से अभी तक	1

नीति में यह भी वर्णित था कि उपरोक्त वर्णित अवधियों में यदि दुरुपयोग का समय एक से अधिक अवधियों के अंतर्गत आता है तो मामले में समयावधि का कारक जिसमें दुरुपयोग की अवधि ज्यादा बड़ी होगी वही लिया जाएगा।

अनुलग्नक -X

(पैरा 4.11 में संदर्भित)

तीन खेल परिसरों में प्रति केवीए लागूदर, ली गई संविदागत माँग, इष्टतम आवश्यक संविदागत माँग, अप्रयुक्त शेष संविदागत माँग के विवरण

(केवीए में संविदागत माँग)

क्रम सं.	विवरण	रोहिणी खेल परिसर	मेजर ध्यान चंद खेल परिसर	पूर्वी दिल्ली खेल परिसर
1.	ली गई संविदागत माँग	295	191	276
2.	इष्टतम आवश्यक संविदागत माँग	155	130	102
3.	अप्रयुक्त शेष संविदागत माँग	140	61	174

परिहार्य व्यय का अभिकलन

क्रम सं.	अवधि	अवधि के लिए लागू प्रति केवीए दर (₹ में)	इस अवधि के महीने	अधिक केवीए	धनराशि (₹ में)
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (आरएससी)					
1.	जून 2004 से सितंबर 2011	150	88	140	18,48,000
2.	अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017	125	71	140	12,42,500
3.	सितंबर 2017 से मार्च 2018	130	07	140	1,27,400
कुल					32,17,900
मेजर ध्यान चंद खेल परिसर (एमडीसीएससी)					
4.	अप्रैल 2010 से सितंबर 2011	150	18	61	1,64,700
5.	अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017	125	71	61	5,41,375
6.	सितंबर 2017 से मार्च 2018	130	07	61	55,510
कुल					7,61,585
पूर्व दिल्ली खेल परिसर (पीडीकेपी)					
7.	जनवरी 2011 से सितंबर 2011	150	09	174	23,49,00
8.	अक्टूबर 2011 से अगस्त 2017	125	71	174	15,44,250
9.	सितंबर 2017 से मार्च 2018	130	07	174	1,58,340
कुल					19,37,490
कुल योग					59,16,975

अनुलग्नक-XI

(पैरा 7.2 में संदर्भित)

ग्रोस बर्थ आऊटपुट के संदर्भ में कम निष्पादन के लिए रियायतग्राहियों से वसूल किया जाने वाला परिनिर्धारित नुकसान

अवधि	परिनिर्धारित नुकसान (₹)
जीसीबी बर्थ	
अप्रैल 2013 से जून 2013	1,18,54,221
जुलाई 2013 से सितंबर 2013	95,96,540
अक्टूबर 2013 से दिसंबर 2013	46,33,997
जनवरी 2014 से मार्च 2014	0
अप्रैल 2014 से जून 2014	1,20,41,891
जुलाई 2014 से सितंबर 2014	1,86,40,592
अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2014	1,35,17,866
जनवरी 2015 से मार्च 2015	1,17,82,822
अप्रैल 2015 से जून 2015	2,12,86,968
जुलाई 2015 से सितंबर 2015	1,15,33,352
अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2015	82,34,467
जनवरी 2016 से मार्च 2016	62,56,357
अप्रैल 2016 से जून 2016	49,32,617
जुलाई 2016 से सितंबर 2016	1,18,13,360
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	22,27,030
जनवरी 2017 से मार्च 2017	14,40,287
अप्रैल 2017 से जून 2017	55,13,905
जुलाई 2017 से सितंबर 2017	55,53,804
अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017	1,81,72,647
जनवरी 2018 से मार्च 2018	2,06,17,362
कुल जीसीबी बर्थ के लिए (ए)	19,96,50,085
डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ	
जनवरी 2016 से मार्च 2016	19,52,392
अप्रैल 2016 से जून 2016	14,00,833
जुलाई 2016 से सितंबर 2016	15,12,593
अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2016	12,03,846
जनवरी 2017 से मार्च 2017	1,34,198

अप्रैल 2017 से जून 2017	9,91,689
जुलाई 2017 से सितंबर 2017	31,90,658
अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017	42,66,733
जनवरी 2018 से मार्च 2018	17,86,740
कुल डब्ल्यूक्यू-6 बर्थ के लिए (बी)	1,64,39,682
ईक्यू-10 बर्थ	
जनवरी 2017 से मार्च 2017	97,975
अप्रैल 2017 से जून 2017	1,30,341
जुलाई 2017 से सितंबर 2017	2,58,514
अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017	94,603
जनवरी 2018 से मार्च 2018	37,454
कुल ईक्यू-10 बर्थ के लिए (सी)	6,18,887
कुल योग (ए+बी+सी)	21,67,08,654

नोट: निर्धारित नुकसान की गणना एमसीए के परिशिष्ट 15 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, जिसके अनुसार रियायतग्राही द्वारा औसत निष्पादन में प्रत्येक 10 प्रतिशत की कमी हेतु संबंधित तिमाही के सकल राजस्व का एक प्रतिशत निर्धारित नुकसान देय होगा।

अनुलग्नक-XII

(पैरा 7.3 में संदर्भित)

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा रियायती करारों में दण्डात्मक धारा सम्मिलित न करने के कारण हुए राजस्व के नुकसान को दर्शाती विवरणी

वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारम्भ की तिथि	अवधि	न्यूनतम गारंटीत कार्गो (एमजीसी) (टन में)	संभाला गया कार्गो (टन में)	एमजीसी प्राप्त करने में कमी (टन में)	अर्जित रॉयल्टी (₹)	दर प्रति टन (₹)	राजस्व की हानि (₹ करोड में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(4)	(8) = (5)x(7)
इक्यु-6 बर्थ							
जुलाई 2015	अगस्त 2015 से जुलाई 2016	5,20,000	2,22,929	2,97,071	2,73,46,303	122.67	3.64
	अगस्त 2016 से जुलाई 2017	5,20,000	5,11,014	8,986	4,87,82,343	95.46	0.08
						कुल (ए)	3.72
इक्यु-10 बर्थ							
जुलाई 2017	जुलाई 2017 से जून 2018	4,60,000	2,29,690	2,30,310	46,27,875	20.15	0.46
						कुल (बी)	0.46